

## राष्ट्रीय आय लेखांकन ( National Income Accounting )

- राष्ट्रीय आय लेखांकन का तात्पर्य उन विधियों या तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए होता है । जिस प्रकार एक व्यक्ति या एक संस्था की आय की गणना की जा सकती है , ठीक उसी प्रकार एक देश की आय की भी गणना की जा सकती है । साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है ।
- राष्ट्रीय आय लेखांकन के विभिन्न तरीकों को समझने से पहले हमारे लिए अर्थव्यवस्था की समग्र गतिविधियों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है । नीचे दिया गया फ्लो चार्ट एक खुली अर्थव्यवस्था में संसाधनों ( धन/आय ) के चक्रीय प्रवाह को दर्शाता है ।

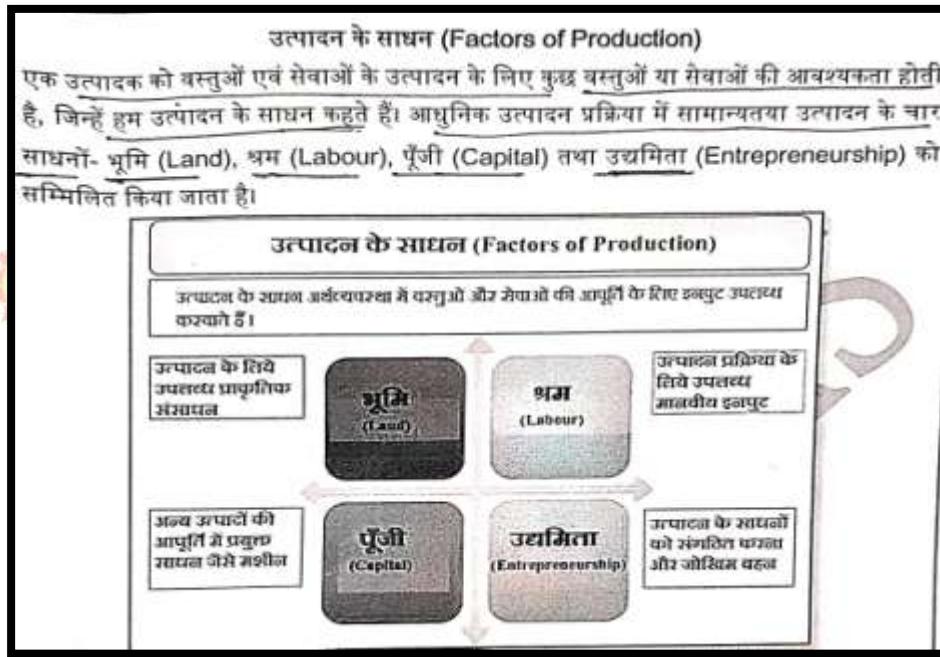


- उत्पादन , उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं । इन्हीं के संचालन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बीच लेन—देनों

मे आय और व्यय के प्रवाह का चक्रीय स्वरूप हो जाता है । यह दो सिद्धांतों पर आधिरित है :

- क्रेता का व्यय विक्रेता का आय बन जाती है और
- वस्तुएँ और सेवाएं विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होती है ।  
इनके लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा मे अर्थात् क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है । इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह ( वास्तविक प्रवाह ) एक दिशा मे होते हैं तो दूसरी ओर मौद्रिक भुगतान के रूप मे प्रवाह ( मौद्रिक प्रवाह ) होते हैं । ये दोनों प्रवाह एक साथ मिलकर चक्रीय प्रवाह कहलाते हैं ।
- परिवार क्षेत्रक , फर्म (व्यापारिक कंपनी ) से वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदता है । वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से जो आय प्राप्त होता है उनका प्रयोग फर्म के स्वामियों द्वारा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने , भू-स्वामी को किराया देने और स्वयं को लभांश का वितरण आदि करने मे किया जाता है । इस प्रकार सकल घरेलू उत्पादन ( **GDP** ) वस्तुतः वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए लोगो द्वारा बाजार मे व्यय की गई कुल राशि के बराबर होता है । साथ ही यह उत्पादन के कारकों के लिए बाजार मे फर्मों द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी , किरायों और लाभ के बराबर भी होती है ।

- उनर्युक्त पलो चार्ट द्वारा सामान्य अर्थव्यवस्था में परिवारों एवं फर्मों के मध्य हुए सभी लेनदेन का वर्णन किया गया है। यह पलो चार्ट इस विषय वस्तु को यह मानकर सरलीकृत करता है कि सभी वस्तुएं एवं सेवाएं लोगों द्वारा खरीदी जाती है और लोग अपनी संपूर्ण आय का खर्च करते हैं।
- इसमें यह दर्शाया गया है कि आय/धन लगातार लोगों से फर्मों की ओर गतिशील होता है और पुनः लोगों के पास वापस आता है।



- धन के इस प्रवाह को (GDP) द्वारा मापा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था के लिए इसकी गणना निम्नलिखित दो तरीकों से की जा सकती है :
  - लोगों द्वारा किये गये कुल व्यय को जोड़कर या

- फर्मों द्वारा भुगतान की गई कुल आय ( मजदूरी , किराया , लाभ ) को जोड़कर
- चूंकि किसी अर्थव्यवस्था से सभी व्यय वस्तुतः किसी आय के रूप में होते हैं , इसलिए हम किसी पद्धति से **GDP** की गणना करें , **GDP** का मान समान ही प्राप्त होता है ।

### **खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था ( Open and closed Economy )**

- खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसके विश्व के अन्य देशों से आर्थिक संबंध होते हैं । आज विश्व के अधिकांश देश खुली अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं । जिन देशों ( अर्थव्यवस्थाओं ) के शेष विश्व से कोई आर्थिक लेन—देन नहीं होते , उन्हें हम बंद अर्थव्यवस्थाएँ कहते हैं । वर्तमान समय में विश्व में ऐसे किसी देश का होना बहुत कठिन है ।
- एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम उसे देश की सीमाओं के अंतर्गत होने वाली आर्थिक गतिविधियों का ही विश्लेषण करते हैं । ऐसी अर्थव्यवस्था में आयात , निर्यात एवं विदेशी निवेश शून्य होता है ।
- इसके विपरीत खुली अर्थव्यवस्था में हम एक देश के आर्थिक लेन—देन का अध्ययन दूसरे देशों के साथ करते हैं , अर्थात् इसमें विदेशी क्षेत्र भी जुड़ जाता है । इसमें आयात , निर्यात , विदेशी निवेश एवं विनिमय दर जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का भी विश्लेषण किया जाता है ।

## राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व

- **अंतराष्ट्रीय तुलना :-** राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर और उस देश के विकास का मापन संभव होता है। इसका प्रयोग विभिन्न देशों के लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किया जा सकता है।
- **व्यावसायिक निर्णय :-** राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के सापेक्ष योगदान और इन क्षेत्रकों की अभीष्ट क्षमता है। यह क्षमता व्यवसायी वर्ग का भविष्य में उत्पादन हेतु विभिन्न क्षेत्रों के चयन करने और योजना निर्माण में मार्गदर्शन करती है।
- **नीति निर्माण :-** राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था में आय एवं संसाधनों के वितरण पर प्रकाश डालता है, जिससे सरकार को देश में समानता को बढ़ावा देने और विकासात्मक कार्यों हेतु संसाधनों के समूचित आवंटन में मदद मिलती है।
- **नीतिगत मूल्यांकन :-** राष्ट्रीय आय लेखांकन, विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों और विफलताओं को उजागर करता है। इस प्रकार यह सरकारी नीतियां के मूल्यांकन में लोगों की मदद करता है।
- **वार्षिक बजट :-** राष्ट्रीय आय लेखांकन से सरकार को अपने बजटीय नीति को आकार देने में मदद मिलती है। आय एवं रोजगार की अनिश्चिता को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आय लेखांकन

विश्लेषण करती है और तत्पश्चात आवश्यकतानुसार अपनी कर एवं उधार लेने हेतु नीति बनाती है। किसी अर्थव्यवस्था में मंदी या मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने के लिए सरकार घाटे या अधिशेष वाला बजट पेश करती है।

- **राष्ट्रीय व्यय में सहायक :-** राष्ट्रीय आय के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय व्यय को निवेश और उपभोग में कैसे विभाजित किया जाए। आय लेखांकन से समष्टि अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि को समझाने में मदद मिलती है।



CAREER FOUNDATION

## 2. राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं ( Concepts of National Income)

समय के साथ—साथ राष्ट्रीय आय की गणना की विधि में कई सुधार हुए हैं। किसी देश की आय की गणना हेतु अर्थशास्त्रियों द्वारा चार प्रकार की अवधारणाओं – **GDP** , **GNP** , **NDP** और **NNP** की उपयोग किया जाता है।

## सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) :-

- किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि ( एक वर्ष या तिमाही या अर्ध-वार्षिकी ) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं । भारत के लिए यह समयावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है ।
- अतः यह किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों या गैर-निवासियों या फर्मों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है । सरल शब्दों में कहें तो यह किसी व्यक्ति या फर्म की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का मापन करता है ।
- उदाहरण के लिए , एक जापानी कंपनी द्वारा भारत में विनिर्मित कारों को भारत के **GDP** में सम्मिलित किया जाएगा जबकि टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटेन में विनिर्मित जगुआर कारों को भारत के **GDP** में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।
- **GDP** केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन को ही संदर्भित करता है । इसमें केवल पूर्ण या अंतिम वस्तुओं को इसलिए सम्मिलित करते हैं ताकि ( वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित ) कच्चे माल, मध्यवर्ती

उत्पाद और अंतिम उत्पादों की दोहरी या तिहरी गणना से बचा जा सके ।

### आर्थिक या घरेलू सीमा

सिस्टम ऑफ नेशनल एकाउन्ट्स मे घरेलू सीमा के रूप मे परिभाषित किया गया है । राष्ट्रीय आय लेखांकन में इसका अलग अर्थ तथा महत्व है । घरेलू या आर्थिक सीमा वैसे देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित होती है तथा आर्थिक सीमा में भौगोलिक सीमा को सम्मिलित किया जाता है पर आर्थिक सीमा तथा भौगोलिक सीमा बिल्कुल एक ही नहीं होगी । आर्थिक सीमा के अंतर्गत निम्नाकिंत को सम्मिलित किया जाता है –

- वायु क्षेत्र तथा क्षेत्रीय जल क्षेत्र जिस पर मत्स्यन , ईधन या खनिज दोहन का अधिकार राष्ट्र का हो ।
- शेष विश्व मे सीमान्तर्गत विदेशी अंतःक्षेत्र जिसके अंतर्गत दूतावास , मिलिट्री बेस , प्रवजन कार्यालय भी सम्मिलित है ।
- मुक्त क्षेत्र , कस्टम के नियंत्रण में आने वाले समुद्रतट के उद्यम , पर इसके अंतर्गत देश की सीमा में दूसरी सरकारों या देशों के विदेशी अंतःक्षेत्र नहीं आयेंगे जिनमें उनके दूतावास हैं या जहाँ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें या उनके कार्यालय या अन्य देशों के मिलिट्री बेस है ।

इस प्रकार जहां तक आर्थिक सीमा का प्रश्न है इसमें देश की भौगोलिक सीमा का वह भाग नहीं सम्मिलित होगा जो दूसरे देशों को विदेशी अंतः

क्षेत्र के रूप मे दूतावास या अन्य कार्यालयों के लिए दिए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए गए हैं या अन्य जिनका उल्लेख ठीक ऊपर किया गया है । इस दृष्टि से आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से छोटी होगी पर इसमें विश्व के अन्य देशों के भी ऐसे हिस्से जो इस देश के मिलिट्री बेस , दूतावासों के रूप में विदेशी अंतः क्षेत्र'क रूप में प्राप्त हुए होंगे उन्हे उक्त देश की आर्थिक सीमा (घरेलू सीमा ) मे सम्मिलता किया जायेगा , यद्यपि वह दूर—दराज तक भी किसी रूप मे उस देश की भौगोलिक सीमा का भाग नहीं हो सकता । इस दृष्टि से कुल आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से बड़ी होगी ।

- देश की भौगोलिक , राजनैतिक एवं सामुद्रिक सीमा ।
- मछली पकड़ने की नौकाएं , दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलने वाले जहाज , वायुयान आदि ।
- पेट्रोलियम एवं गैस अन्वेषण के लिए समुद्र में स्थित स्थान ।
- देश के विदेशों में दूतावास , वाणिज्यिक दूतावास एवं सैनिक अड्डें ।
- उदाहरण के लिए , ऑटोमोबाइल के मूल्य में पहले से ही उसके विनिर्माण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले इस्पात , कांच , रबड़ और अन्य घटकों के मूल्य सम्मिलत होते हैं । इन्हें नीचे संक्षिप्त में समझाया गया है :

- **अंतिम उत्पाद** : इसका अर्थ है 'अंतिम उपभोग के लिए क्रया की गयी वस्तुएं एवं सेवाएं ।
- **मध्यवर्ती वस्तुएं** अथवा उत्पादन के कारक या कच्चा माल : किसी अन्य उत्पाद के उत्पादन में इनपुट या आगत या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त उत्पाद को मध्यवर्ती वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है ।
- दोहरी गणना से बचाव के दो तरीके हैं :
  - केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना करना , या
  - किसी वस्तु के उत्पादन के आरंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक हुए मूल्य वर्धन की गणना करता । उसके बाद उक्त वस्तु के विक्रय मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा देना ।



- कोई वस्तु अंतिम है या माध्यमिक , यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह वस्तु उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में आ रही या उपभोग हेतु प्रयोग आ रही है । एक ही वस्तु किसी स्थिति में अंतिम होगी तो दूसरी स्थिति में माध्यमिक हो सकती है ।
- जैसे बेकरी में ब्रेड बनाने में प्रयोग में आने वाला आटा माध्यमिक वस्तु है , जबकि घर में रोटी बनाने में प्रयोग में आने वाला आटा उपभोग वस्तु (अन्त्य) है ।

## . सांकेतिक GDP एवं वास्तविक GDP ( Nominal & Real GDP)

- **सांकेतिक GDP :** जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो वह चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् सांकेतिक GDP कहलाता है ।
- **वास्तविक GDP :** जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है , तो उसे स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अथवा वास्तविक GDP कहते हैं । अर्थात् वास्तविक GDP द्वारा वर्तमान वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के कीमतों पर की जाती है । उल्लेखनीय है कि आधार वर्ष पर मूल्य स्थिर होते हैं ।
- **वास्तविक GDP वस्तुतः** GDP की गणना करने का एक बेहतर तरीका है क्योंकि एक विशेष वर्ष में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण GDP में अचानक उछाल देखा जा सकता है । इसलिए , वास्तविक GDP हमें मुद्रास्फीति और मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन के बावजूद, उत्पदन में हुई वास्तविक वृद्धि या कमी को निर्धारित करने में मदद करता है ।
- इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए , आप एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए जो केवल सेब का उत्पादन करती है । मान लीजिए कि वर्ष 2010 के दौरान एक अर्थव्यवस्था में 100 सेब उत्पादित हुए थे और

प्रत्येक सेब की लागत 1 डॉलर थी । इस प्रकार वर्ष 2010 में उक्त अर्थव्यवस्था का सांकेतिक **GDP** 100 डॉलर ( 1 डॉलर को 100 से गुणा करना ) होगी । जब मान डॉलर तक बढ़ गई । अब वर्ष 2015 के लिए सांकेतिक **GDP** 150 डॉलर ( 3 डॉलर को 50 से गुणा करने पर प्राप्त ) होगा । इस प्रकार हमें यह प्रतीत होता है कि 2010 की तुलना में 2015 में **GDP** में वृद्धि हुई है , परंतु वास्तव में 2015 के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कमी आई है ।

- अब यदि वर्ष 2010 को आधार वर्ष के रूप में मान लिया जाए तो , वर्ष 2010 के लिए वास्तविक **GDP** 100 डॉलर हो जाएगी जबकि वर्ष 2015 के लिए यह 2010 की स्थिर कीमतों पर ( आधार वर्ष की कीमत पर ) 50 डॉलर होगी । इस प्रकार स्पष्ट है कि यहां वास्तविक **GDP** में गिरावट अर्थव्यवस्था में उत्पादन में गिरावट के अनुपात में है । अतः वास्तविक **GDP** किसी भी अर्थव्यवस्था की सांकेतिक **GDP** की तुलना में एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करता है । (आधार वर्ष को आगे विस्तार में समझाया गया है )

## 2.2 सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP )

- GNP और GDP की अवधारणायें परस्पर घनिष्ठ रूप संबंधित हैं।  
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि GDP की अवधारणा की अर्थ एक निश्चित समयवधि में किसी देश की घरेलू सीमा निवासियों और गैर-निवासियों दोनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों से है। इस प्रकार GDP में 'उत्पादन किसके द्वारा किया गया है' के स्थान पर उत्पादन कहां पर हुआ है पर ध्यान दिया जाता है।
- दूसरी ओर , घरेलू सीमा के भीतर या बाहर एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को GNP कहते हैं। इस प्रकार जब भारत GNP की गणना की जाती है तो इसके अंतर्गत भारत के भीतर तथा विश्व के अन्य देशों में भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्यों की भी गणना की जाती है।
- आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे सरल तरीके से समझते हैं, जैसे— माइक्रोसॉफ्ट USA की एक फर्म है। जब यह भारत में कोई कंपनी खोलती है, तो उसके उत्पादन का मूल्य भारत के GDP में सम्मिलित किया जाएगा लेकिन भारत की GNP की गणना करते समय इसक सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी तरह जब इंफोसिस या

TCS जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपनी सेवाएँ उपलब्ध करवाती हैं ,तो इन सेवाओं का मूल्य भारत के **GDP** में सम्मिलित नहीं किया जाता है , लेकिन भारत के **GNP** की गणना करते समय उन्हें सम्मिलित किया जाता है । इस प्रकार **GDP** 'जहाँ उत्पादन होता है ' उससे संबंधित है । जबकि दूसरी ओर , **GNP** 'जो उत्पादन करते हैं ' से संबंधित है ।

**GNP = GDP + विदेश से निवल साधन आय ( Net Factor**

**Income from Abroad : NFIA )**

- 
- यदि किसी अर्थव्यवस्था में **FDI** का अंतर्प्रवाह काफी अधिक है तथा बहिर्प्रवाह अम्यत्प है तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतया उक्त देश की **GDP** उसके **GNP** की तुलना में अधिक होगी । वहीं दूसरी ओर , यदि किसी देश के नागरिक अत्यधिक संख्या में विदेश जाते हैं एवं वहां आर्थिक गतिविविधयों में संलग्न होकर अपने गृह देश में बहुत अधिक पैसा भेजते हैं , जबकि उसे में विदेशी नागरिकों की आर्थिक गतिविधियाँ नान्य हैं ( अर्थात् विदेशी नागरिक यहाँ से अपने गृह देश में कम पैसा भेजे हैं) तो ऐसी परिस्थितियों में उक्त देश की **GNP** उसके **GDP** से अधिक होगी । भारत की बात करें तो इसकी **GNP** इसके **GDP**

तुलना में कम हैं क्योंकि भारत मे विदेशों से प्राप्त निवल आय सदैव नकारात्मक रही है ।

- यद्यपि **GDP** का उपयोग किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है , किंतु कुछ अर्थशास्त्री इसे एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करने वाला नही मानते हैं । चूंकि **GDP** की गणना में विदेशी कंपनियों द्वारा किसी देश मे अर्जित लाभ को भी सम्मिलित किया जाता है और ये लाभ इन विदेशी निवेशको द्वारा अपने गृह देश ( या अन्य देश में भी ) में पुनः प्रेषित कर दिए जाते हैं । अतः ऐसी स्थिति मे यदि देश के बाहर भेजा जाने वाला उक्त लाभ किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेशों मे अर्जित आय एवं विदेशी परिसंपत्तियों से हुए लाभ की तुलना में बहुत अधिक हैं , तो निश्चित ही उसे देश की **GNP** उसे **GDP** की तुलना में अत्यंत कम होगी ।

#### 2.2.1. विदेशो से प्राप्त साधन ( कारक ) आय ( Net Factor Income from Aboroad : NFIA )

- विदेश से प्राप्त साधन आय ( **NFIA** ) वस्तुतः बहुत ही कम है क्योंकि नागरिकों द्वारा सूजित (विदेशो से) साधन आय और विदेशियों को दिए जाने वाले भुगतान कमोबेश एक—दूसरे को प्रतिसंतुलित कर देते है ।

संक्षेप में , **NFIA = GNP-GDP**

### 2.3 GDP वैशिक स्तर पर सबसे स्वीकार्य संकेतक क्यों है ?

- **GDP** संवृद्धि दर (आर्थिक संवृद्धि का मापक) वस्तुतः किसी राष्ट्र के कल्याणकारी गतिविधयों हेतु एक प्रमुख संकेतक होती है । साथ ही यह 'विकास' के कई अन्य मापकों , जैसे—साक्षरता , स्वास्थ्य सुविधाएं आदि संकेतकों से भी संबंधित होता है ।
- वर्तमान मे यह स्पष्टतया परिभाषित है और इसकी गणना करना अपेक्षाकृत सरल है ।
- चूंकि यह एक मौद्रिक/गणितीय/लेखा गणना है औंश्र इसकी एक स्थातिप पद्धति भी विद्यमान है , अतः यह वस्तुनिष्ठ है ( इसके विपरीत "खुशहाली" और " राजनीतिक स्वतंत्रता" जैसे सूचक व्यक्तिनिष्ठ है , जिन्हें मापना कठिन है) ।
- **GDP** का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और लगभग सभी देश अपने राष्ट्रीय आय की गणना में इसी पद्धति का उपयोग करते हैं । अतः इसके माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य तुलना करने में सुविधा होती है ।
- अपने वृहद इतिहास और मानक पद्धति के कारण **GDP** को नीति निर्माताओं द्वारा समझना अपेक्षाकृत आसान है ।

## 2.4 मूल्यहास ( Depreciation )

- उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त सभी मशीनों और उपकरणों में कुछ टूट-फूट होती हैं। आर्थिक बोल-चाल की भाषा में, ऐसी पूंजीगत वस्तुओं की वह हानि जिसका प्रत्येक अर्थव्यवस्था को टूट-फूट के रूप में भुगतान पड़ता है, मूल्यहास कहलाता है।
- अर्थव्यवस्था में उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं के एक भाग को इस टूट-फूट के बदले में रखा जाना चाहिए, अन्यथा एक राष्ट्र की उत्पादक क्षमता कम हो जाएगी। इस प्रकार रखे गए पूंजी को कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कहते हैं।
- इस प्रकार ऐसे परिदृश्य में किसी फर्म में हुई निवेश व्यय ( **Investment expenditure** ) को दो भागों में रखा जाता है। इसके एक भाग का उत्पादन के लिए नई पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को खरीदने में उपयोग किया जाता है। इसे निवेश कहा जाता है, क्योंकि इससे फर्म की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जा सकता है।
- इसके दूसरे भाग को उपयोग में लाई गई पूंजीगत वस्तुओं को प्रतिस्थापित करने या मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं के रखरखाव के लिए

व्यय किया जाता है। इस हेतु हुए व्यय को मूल्यहास व्यय कहा जाता है।

- किसी फर्म द्वारा इन दोनों राशियों के रूप में किए गए निवेश को सकल निवेश कहते हैं।

$\text{सकल निवेश} = \text{निवल निवेश} + \text{मूल्यहास}$ $(\text{Gross Investment} = \text{Net Investment} + \text{Depreciation})$ या $\text{निवल निवेश} = \text{सकल निवेश} - \text{मूल्यहास}$ $(\text{Net Investment} = \text{Gross Investment} - \text{Depreciation})$
---

यदि निवल निवेश सकारात्मक है तो यह राष्ट्र की उत्पादन और आउटपुट को बढ़ाता है। इसे किसी छोटे फर्म या एक संयंत्र के स्तार पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। अर्थात् एक फर्म के लिए किसी भी वर्ष में स्थापित नई मशीनों की संख्या उन मशीनों की तुलना में अधिक होनी चाहिए जो उस वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई हैं।

सामान्यतया सरकार ही किसी अर्थव्यवस्था में मूल्यहास की दर तय करती है और इसकी घोषण करती है कि किस संपति में कितना मूल्यहास होग तथा इसकी एक सूची भी प्रकाशित की जाती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा इसका उपयोग भिन्न-भिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में मूल्यहास के वास्तविक स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

## **2.5. निवल घरेलू उत्पाद ( NDP )**

'मूल्यहास की राशि को समायोजित करने के बाद जब GDP की गणना की जाती है तो ऐसे GDP को ही NDP कहते हैं । वस्तुतः NDP , निवल GDP ही है , (अर्थात् GDP - मूल्यहास ) साधरण शब्दों में , वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान परिसंपत्तियों में टूट-फूट (मूल्यहास) की कुल राशि को GDP में से घटाने पर NDP प्राप्त होता है ।

$$\boxed{\mathbf{NDP = GDP - मूल्यहास} \quad (\mathbf{NDP= GDP- Depreciation})}$$

- किसी अर्थव्यवस्था की NDP हमेशा GDP की तुलना में कम होती है , क्योंकि मूल्यहास को कभी भी शून्य तक नहीं लाया जा सकता है तथा यह हमेशा धनात्मक रहता है ।

## **2.6. निवल राष्ट्रीय उत्पाद ( NNP )**

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( GNP) में से मूल्यहास को घटाकर NNP प्राप्त किया जाता है ।

$$\boxed{\mathbf{NNP = GNP - मूल्यहास} \quad (\mathbf{NNP=GNP- Depreciation})}$$

- विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए **NDP** और **NNP** की अवधारणाओं का उपयोग नहीं किया जाता है , क्योंकि मूल्यहास की गणना की विधि अलग—अलग राष्ट्रों में भिन्न—भिन्न तरीके से होती है ।

## बाजार मूल्य और साधन (कारक) लागत की अवधारणा

### ( The Concept of Market Price and Factor Cost )

- बाजार मूल्य वस्तुतः वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक लेनदेन के मूल्य को संदर्भित करता है । इसमें अप्रत्यक्ष कर तथा सब्सिडी सम्मिलत होते हैं । अप्रत्यक्षय कर वस्तु के मूल्य को बढ़ा देते हैं और सब्सिडी इसको कम करती है ।
- साधन लागत वस्तुतः वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त या उपभोग की गयी उत्पादन के सभी कारकों की लागत को संदर्भित करता है । इसमें भूमि के लिए किराया , पूंजी के लिए ब्याज, श्रम के लिए मजूदूदी और उद्यमिता के लिए लाभ सम्मिलत होते हैं । वास्तविक उत्पादन लागत है जिस पर किसी फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पाद किया जाता है । साधन लागत पर गणना करते समय अप्रत्यक्ष करों की घटाया जाता है तथा सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी को जोड़ा जाता है ।

दूसरे शब्दों में ,

साधन लागत (FC) = बाजार मूल्य – निवल अप्रत्यक्ष कर

{ Factor cost (FC) = Market Price - Net  
Indirect Taxes }

जहाँ ,

निवल अप्रत्यक्ष कर ( NIT ) = अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी

{ Net Indirect Taxes ( NIT ) = Indirect Taxes -  
Subsidies }

इसलिए

साधन लागत = बाजार मूल्य -अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

इस अवधारणा का उपयोग करके , कारक या साधन लागत पर GDP-  
की गणना बाजार मूल्य पर GDP में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर  
भी की जा सकती है ।

साधन लागत पर GDP = बाजार मूल्य पर GDP - निवल अप्रत्यक्ष कर

या

साधन लागत पर **GDP** = बाजार मूल्य पर **GNP** - निवल अप्रत्यक्ष कर

साधन लागत पर **NDP** = बाजार मूल्य पर **NDP** - निवल अप्रत्यक्ष कर

साधन लागत पर **NNP** = बाजार मूल्य पर **NNP** - निवल अप्रत्यक्ष कर

## राष्ट्रीय आय ( National Income )

- राष्ट्रीय आय वस्तुतः (एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान) एक देश के निवासियों द्वारा अपने गृह देश या विदेशों में अपनी भूमि , श्रम , पूँजी और उद्यमी प्रतिभा द्वारा अर्जित कारक/साधन आय का कुल योग है। यह साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है । इसे बाजार मूल्य पर **NNP** में से निवल अप्रम्यक्ष कर को घटाकर (जैसा कि ऊपर बताया गया है ) प्राप्त किया जाता है ।

साधन लागत पर राष्ट्रीय आय = बाजार मूल्य पर NNP – अप्रत्यक्ष कर  
+ सब्सिडी

{ National Income at Factor cost = NNP at Market  
Price - Indirect Taxes + Subsidies }

राष्ट्रीय आय के रूप में साधन लागत NNP को अपनाये जाने के निम्नलिखित कारण हैं :

- NNP देश के सभी निवासियों द्वारा अर्जित आय को दर्शाता है | यह सही भी है, क्योंकि इसमें विदेशियों द्वारा अर्जित आय को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है | इस प्रकार NNP को NDP से अधिक वरीयता प्रदान की जाती है |
- साधन लागत को प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि निवल अप्रत्यक्ष कर, जैसे—बिक्री कर, उत्पादन शुल्क आदि उत्पादन के साधनों/कारों के लिए किए गए भुगतान नहीं है | अर्थात्, उत्पादन के कारण को ही इसमें शामिल किया जा सकता है |
- विभिन्न देशों के करों में समानता नहीं है |

- भारत जैसे विकासशील देशों में प्रायः वस्तुएं कीमतों के साथ मुद्रित नहीं की जाती हैं ।

## हस्तांतरण भुगतान ( Transfer Payments )

- हस्तांतरण भुगतान का तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को किए गए भुगतानों से हैं , जिसके बदले में इन व्यक्तियों द्वारा कोई आर्थिक गतिविधि या सेवा प्रदान नहीं की जाती है ।  
वृद्धावस्था पेशन , छात्रवृत्ति आदि हस्तांतरण भुगतान के कुछ उदाहरण हैं ।



## व्यक्तिगत आय ( Personal Income )

- व्यक्तिगत आय , सभी व्यक्तियों या परिवारों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय होती है असमें LPG सब्सिडी जैसे हस्तांतरण भुगतान भी शामिल हैं । परिवारां द्वारा कल्याणकारी भुगतान प्राप्त किए जाते हैं , परन्तु ये भुगतान राष्ट्रीय आय के घटक नहीं होते हैं क्योंकि ये हस्तांतरण भुगतान होते हैं ।
- इसी प्रकार , राष्ट्रीय आय लेखांकन में कुछ ऐसी आय शामिल कर ली जाती हैं जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय होती हैं परन्तु जो व्यक्तियों

को वास्तव में प्राप्त नहीं होती हैं , जैसे—अवितरित लाभ , सामाजिक सुरक्षा हेतु कर्मचारी का योगदान , कॉर्पोरेट इन्कम टैक्स आदि इन्हें राष्ट्रीय में से घटाया जाता है । इस प्रकार व्यक्तिगत आय है :

**व्यक्तिगत आय = राष्ट्रीय आय + हस्तांतरण भुगतान -कॉरपोरेट प्रतिधारित आय , आयकर , सामाजिक सुरक्षा कर**

{ **PI = NI + transfer payments - corporate retained earnings , income taxes , social security taxes }** }

व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ( **Disposable Personal Income ?** )



- व्यक्तिगत प्रयोज्य (व्यय योग्य) आय से आशय किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध वास्तविक व्यय योग्य राशि से है । इसका अर्थ व्यक्तिगत रूप से भुगतान किए गए करों , जैसे – आय कर , संपति कर , प्रोफेशनल टैक्स आदि के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास बची हुई राशि से है ।

इस प्रकार ,

**व्यक्तिगत प्रयोज्य आय = व्यक्तिगत आय - व्यक्तिगत कर { **DPI= PI - Personal Taxes**  }**

- यह अवधारणा व्यक्तियों के व्यय और बचत व्यवहार को जानने और समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह वह राशि है, जिसको खर्च किया या बचाया जा सकता है।

**प्रोज्य आय = उपभोग + बचत ( Disposable Income =  
consumption + Savings )**

	मूल्यदाम (Depreciation)	बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product)	विदेशों में प्राप्त निवालमाध्यन आय (NFIA)
निवल अप्रत्यक्ष कर (NIT)	बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product)		
राष्ट्रीय आय			बाजार मूल्य पर सकल घरेलु उत्पाद (GDP)

चित्र:2 राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं

अभी तक हमनें राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित मापकों की चर्चा की है:

- राष्ट्रीय आय = साधन लागत पर NNP
- साधन लागत पर NNP = बाजार मूल्य पर NNP - निवल अप्रत्यक्ष कर
- साधन लागत पर NDP = बाजार मूल्य पर NDP - निवल अप्रत्यक्ष कर

- निवल अप्रत्यक्ष कर (**NIT**) = अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी
- **NNP = GNP - मूल्यहास**
- **NDP = GDP - मूल्यहास**
- **GNP=GDP + विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय**

## **राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक ( Factor Affecting national Income )**

कोई ऐसे कारक हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं ।

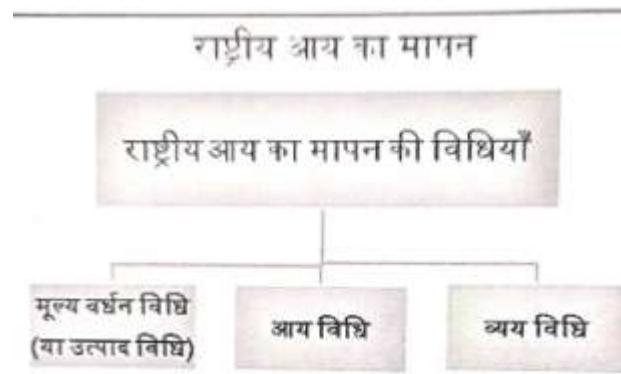
उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :



- **उत्पादन के कारक :** सामान्यतया जब संसाधन अधिक कुशल और समृद्ध होंगे तो निश्चय ही राष्ट्रीय आय या **GNP** का स्तर उच्चतर होगा ।
- **भूमि :** भारी उद्योगों के लिए कोयला , लौह और लकड़ी जैसे संसाधनों की उपलब्धता एवं उन तक पहुंच आवश्यक हैं । दूसरे शब्दों में , इन प्राकृतिक संसाधनाके की भौगोलिक - **GNP** के स्तर को प्रभावित करती है ।

- **पूँजी:** पूँजी आम तौर पर निवेश द्वारा निर्धारित होती है । यह अलग बात है कि निवेश अन्य कारकों पर निर्भर करता है , जैसे—लाभप्रदता , राजनीतिक स्थिरता आदि ।
- **श्रम और उद्यमिता :** मानव संसाधन की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधन की गुणवता या उत्पादकता है । श्रम शक्ति , नियोजन और शिक्षा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और उत्पादन क्षमता को को प्रभावित करती है ।
- **प्रौद्योगिकी :** अल्प प्राकृतिक संसाधनों वाले देशों के लिए यह कारक अधिक महत्वपूर्ण है । प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे हुए या होने वाले विकास और नवाचार के स्तर से राष्ट्रीय आय का स्तर प्रभावित होता है ।
- **सरकार :** सरकार निवेश हेतु अनुकूल कारोबारी परिवेश प्रदान करने मे मदद कर सकती है । यह कानून—व्यवस्था ,विनियमन आदि उपलब्ध कराती है ।
- **राजनीतिक स्थिरता :** एक स्थिर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था संसाधनो के उचित आवंटन में मदद करती है । युद्ध , हमलों और सामाजिक असंतुलन से निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों हतोत्साहित होती है ।

## राष्ट्रीय आय का मापन ( Measurement of National Income )



भारत में **GDP** का आंकलन केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण निम्नलिखित तीन विधियों से किया जाता है :

- मूल्य वर्धन विधि ( या उत्पाद विधि )
- आय विधि
- व्यय विधि

इनमें से किसी विधि को अपनाया जाए , यह आंकड़ों की उपलब्धता एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है ।

## आय विधि( Income Method )

- यह पत्रद्वच्छति फर्मो द्वारा परिवारों को किए गए कुल भुगतानों के योग पर केंद्रित है , जिन्हें साधन भुगतान कहा जाता है । यह राष्ट्रीय आय का मापक है । यह राष्ट्रीय आय का मापक है । राष्ट्रीय से आशय एक देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय से है ।
- उत्पादन के साधन चार प्रकार के होते हैं तथा साधन आय भी चार प्रकार की होती है । भूमि ,श्रम, पूँजी और संगठन उत्पादन के चार साधन हैं तथा लगान , मजदूरी ,ब्याज और लाभ साधन आय के प्रकार हैं ।
- इस आय में अप्रत्यक्ष करों एवं मूल्यहास को जोड़ने तथा सब्सिडी को घटाने पर ( GDP ) प्राप्त होती है ।

**GDP = मजदूरी + लगान + लाभ + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी + मूल्यहास**

- 'लाभ को आगो कर ( प्रॉफिट टैक्स ), सभी शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश और प्रतिधारित लाभ/आय में उपविभाजित किया जा सकता है ।
- अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्रक के योगदान की गणना करने के लिए भारत में इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया है ।

- ऐसी कोई भी आय जिसके कारण वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह नहीं होता है या मूल्य वर्धन नहीं होता है, उसे आय विधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है

## आय विधि ( Expenditure Method )

- **GDP** को किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अन्त्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी अर्थव्यवस्था में तीन मुख्य एजेंसियां –परिवार, फर्म और सरकार होती हैं। ये एजेंसियां वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रया करती हैं।

इस कुल व्यय को निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :

1. उपभोग : घरेलू बाजार में उपभोक्ता परिवारों द्वारा किए गए व्यय तके निजी उपभोग कहते हैं। यह व्यय उपभोक्ता परिवारों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाली फर्मों को भुगतान के रूप में किया जाता है।
2. निवेश व्यय :- निवेश से आशय एक निश्चित अवधि में एक अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में हुई वृद्धि से है। इसमें फर्मों एवं सरकारी क्षेत्रकों द्वारा किए गए निवेश सम्मिलित है।

3. सरकारी व्यय : इस वर्ग में सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर किए गए व्यय को सम्मिलित किया जाता है । पेंशन योजनाओं , छात्रवृत्तियों एवं बेरोजगारी भत्तों आदि को सरकारी व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये व्यय हस्तांतरण भुगतानों के अंतर्गत आते हैं ।

4. निवल निर्यात : विदेश में निर्मित उत्पादों (आयात) पर व्यय से पूँजी का बहिर्प्रवाह होता है, अतः इस व्यय को कुल व्य सं से घटा दिया जाता है । इसके विपरीत घेरलू फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विदेशो में निर्यात से प्राप्त पूँजी को कुल व्यय में जोड़ा जाता है । इन दोनों के संयोजन से निवल निर्यात प्राप्त होता है ।

$$\text{GDP} = \mathbf{C} + \mathbf{I} + \mathbf{G} + (\mathbf{X} - \mathbf{IM})$$



CAREER FOUNDATION  
जुनून राष्ट्र सेवा का

## निम्नांकित को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सम्मिलित किया जाता है :

- आय—गणना वर्ष में उत्पादित अन्त्य वस्तुयें तथा सेवायें ।
- स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन ।
- अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टाक तथ्ज्ञा गणना वर्ष में उत्पादित पर उस वर्ष का न बिका स्टाक ।
- ब्रोकर्स कमीशन क्योंकि वह उत्पादक सेवा है ।
- सैनिक तथा सुरखा सेवायें ।
- सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गयी निःशुल्क सेवायें ।
- लाभांश जो कम्पनियों के ही लाभ के भाग होते हैं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होते हैं ।
- भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान ।
- घिसावट या पूँजी का उपभोग , सकल उत्पाद में तो शामिल होता है पर राष्ट्रीय आय जो शुद्ध उत्पाद होता है , में शामिल नहीं होता है ।
- भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ जो विदेशी आय हैं , राष्ट्रीय आय में से घटा दी जाती है । जबकि यू.एस.ए में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा द्वारा अर्जित लाभ , राष्ट्रीय आय में जोड़ा जायेगा ।
- संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता ।
- विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है ।

## GDP अवस्फीक एवं आधार वर्ष

### GDP अवस्फीतक

यह मुद्रास्फीति को व्यापक रूप से मापने वाला मूल्य सूचकांक है । यह मौद्रिक या चालू मूल्य पर GDP का वास्तविक या स्थिर मूल्य पर GDP के साथ अनुपात को दर्शाता है । 1996 से GDP अवस्फीतक को त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है । इसका कारण यह है कि अर्थशास्त्री वास्तविक मूल्य अनुमानों को प्राप्त करने एवं सांकेतिक मूल्यों के प्रभाव को कम करने के लिए WPI या CPI उपयोग को वरीयता देते हैं ।

- WPI और CPI के विपरीत , GDP अवस्फीतिक वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित समूह पर आधारित नहीं है , अपितु यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सम्मिलित करता है । GDP अवस्फीतिक का एक लाभ यह कि उपभोग के पैटर्न में परिवर्तनया नई वस्तुओं और सेवाओं का प्रवेश अवस्फीतिक में स्वतः ही परिलक्षित होता है । जबकि WPI/CPI के सम्बंध में ऐसा न ही होता है ।

- चालू मूल्यों पर प्रदर्शित **GNP** को स्थिर मूल्यों पर प्राप्त करने के लिये अवस्फीतक का उपयोग किया जाता है ।
- अवस्फीतक एक मूल्य सूचकांक है जो मूल्य में परिवर्तन के कारण **GNP** या **GDP** के मौद्रिक मूल्य में होने वाली परिवर्तनों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लगाया जाता है । इसे मौद्रिक **GDP** को वास्तविक **GDP** या मौद्रिक **GNP** को वास्तविक **GNP** में भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है , जो निम्न है :—
- **GNP अवस्फीतक** = मौद्रिक या चालू मूल्य पर **GNP/वास्तविक या स्थिर मूल्य पर GNP × 100**
- **GDP अवस्फीतक** = मौद्रिक या चालू मूल्य पर **GDP/वास्तविक या स्थिर मूल्य पर GDP × 100**

### आधार वर्ष :—

- **GNP / GDP** की गणना को सरल बनाने हेतु अर्थशास्त्री वास्तविक **GNP / GDP** की गणना के दौरान एक मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं । यह मूल्य सूचकांक वस्तुतः एक संख्या होती है , जो सभी स्तरों पर मूल्यों में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करती है ।

- यह किसी अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर में हुए सामान्य परिवर्तन को दर्शाता है आधार वर्ष वस्तुतः एक सूचकांक के निर्माण के लिए संदर्भ वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला वर्ष होता है , तथा आमतौर पर इसे 100 मान लिया जाता है ।
- हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय लेखा की गणना करने के लिए आधार वर्ष 2004–02 से बदलकर वर्ष 2011–12 कर दिया । आधार वर्ष के चयन के लिए निम्नलिखित आधार है :

  - समष्टि आर्थिक मानदंडो की स्थिरता : यह एक सामान्य वर्ष होना चाहिए जिसमें उत्पादन , व्यापार और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में अत्यधिक परिवर्तन न हो ।
  - आंकड़ो की उपलब्धता : इस वर्ष से संबंधित उपलब्ध आकड़े विश्वसनीय होने चाहिए ।
  - तुलनात्मकता : आधार वर्ष ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही वर्षों के लिये एक समान मानदंडो उपयोग किया जा सके । इसलिए यह हाल ही का कोई वर्ष होना चाहिए , अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

### **राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाई ( भारत के विशेष संदर्भ में )**

राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अर्थशास्त्रियों को कई समस्याओं का सामाना करना पड़ता है , उनमें से कुछ निम्नलिखित है :

- **लेनदेन का गैर-मौद्रिकरण** :- राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान आम तौर पर यह माना जाता है कि वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान मुद्रा के लिए किया जाता है । लेकिन भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में , बड़ी संख्या में आर्थिक लेनदेन वस्तु विनिमय के रूप में होते हैं । **GDP** अनुमानों में इस प्रकार की गतिविधियों का मापन करना अत्यंत कठिन होता है , क्योंकि इसके परिणामस्वरूप **GDP** का मान वास्तविक स्तर की तुलना में कम प्राप्त होता है ।
- **असूचित अवैध आय** :- भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग अवैध या समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में संचालित होता है तथा अर्थव्यवस्था के इस भाग से सृजित आय अलिखित रह जाती है । सटीक **GDP** अनुमानों की गणना करने में यह एक बड़ी समस्या है ।
- **घरेलू , छोटे उत्पादकों आदि से संबंधित आंकड़ों की अनुपलब्धता** :- उत्पादकों की एक बड़ी संख्या पारिवारिक स्तर पर उत्पादन करती है या घरेलू उद्यमों का संचालन करती है । इन उद्यमों से संबंधित आंकड़े प्राप्त करना अत्यंत कठिन है । राष्ट्रीय आय लेखांकन के तहत अर्थव्यवस्था में होने वाली घरेलू सहायता और हाउसकीपिंग आदि जैसी देखभाल संबंधी गतिविधियों को नहीं सम्मिलित किया जाता है , यहां तक कि भारत में गृहणियों द्वारा किया जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को भी **GDP** अनुमानों का हिस्सा नहीं माना जाता है ।

- निरंतर विकसित होते सेवा क्षेत्र से संबंधित आंकड़े की अनुपलब्धता :—  
भारत के सेवा क्षेत्र में चरघातांकी वृद्धि दर देखी गई है । हालांकि सेवा क्षेत्र के कई भागों में मूल्यवर्धन स्टीक सूचनाओं पर आधारित नहीं है , इसीलिए राष्ट्रीय आय का प्राप्त मान वास्तविक मान से कम प्राप्त होता है ।

## GDP मान से नवीनतम विकास

- अब संवृद्धि दर का मापन अंतराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप स्थिर बाजार मूल्यों पर **GDP** के माध्यम से किया जा रहा है । इससे पहले , संवृद्धि दर का मापन स्थिर मूल्यों पर साधन के रूप में किया जाता था ।
- सकल मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार अनुमान अब साधन लागत के स्थान पर आधार मूल्यों पर प्रस्तुत किए जाएंगे ।
- अब **MCA21** डेटाबेस का भी उपयोग किया जाएगा । यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत दाय किया गया कंपनियों का वार्षिक लेखा है । यह कॉर्पोरेट क्षेत्र के कवरेज को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों तक विस्तृत करेगा । इसके अतिरिक्त विनिर्माण कंपनियों के लिए निर्मित यह डेटाबेस इन कंपनियों द्वारा विनिर्माण के अतिरिक्त की गई अन्य गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करने में भी सहायक होगा ।

- स्टॉक ब्रोकर , स्टॉक एक्सचेंजों , परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों , म्यूचुअल फंड एवं पेंशन फंड तथा SEBI , PFRDA और IRDA जैसे नियामक निकायों के खातों से संबंधित जानकारी सम्मिलित करके वित्तीय क्षेत्र का व्यापक कवरेज ।
- स्थानीय निकायों और स्वायत संस्थाओं की गतिविधियों के बेहतर कवरेज , साथ ही इन संस्थानों को प्रदान किए गए लगभग 60 प्रतिशत अनुदान/हस्तांतरण को कवर करना ।

